दैनिक जागरण ; 18-3-16
पृ0-12

आपूर्ति श्रृंखला में छोटे किसान अहम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : किसान आंखों देखी पर यकीन करता है, सुनी-सुनाई पर नहीं। इसी जुमले को ध्यान में रखकर कृषि उन्नति मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें एक लाख किसान हिस्सा लेंगे। कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि जिंस मंडियों के वैश्वीकरण से कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। इसमें किसानों को आधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस करने की जरूरत है। कृषि उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला में छोटे किसानों की भूमिका अहम हो गई है। उनकी जरूरत के कृषि यंत्र चाहिए, जिसका प्रदर्शन इस राष्ट्रीय कृषि मेला में किया जाएगा।

कृषि मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर के इस कृषि मेला का आयोजन राजधानी दिल्ली के बीच बसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किया जा रहा है। 1200 एकड़ में फैले इस संस्थान में लगने वाले इस मेले का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी किसानों से सीधे बातचीत भी करेंगे। कृषि मेला की तैयारियां पिछले छह महीने से चल रही हैं। इसमें खेती-बाड़ी के साथ इससे जुड़े सभी तरह के उद्यमों का प्रदर्शन किया जाएगा। कृषि मंत्री सिंह ने बताया कि इस राष्ट्रीय मेला में देश के सभी ब्लॉक क्षेत्रों से कम से कम दो किसान हिस्सा लेंगे। किसानों की उत्पादकता व आय में वृद्धि से ही खाद्य सुरक्षा व आजीविका की रक्षा संभव है। इसमें छोटे किसानों की सहभागिता महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि खाद्य जिंसों की मंडियों का वैश्वीकरण हो चुका है, जिससे कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है। इस दौर में कृषि क्षेत्र में किसानों की कार्यक्षमता बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी की जरूरत है। उन्होंने बताया कि खाद्य जिंसों की आपूर्ति श्रृंखला में छोटे किसानों को शामिल करने की सख्त जरूरत को देखते हुए उन्हें अवसर प्रदान किया जा रहा है। 19-21 मार्च तक चलने वाले इस जलसे में किसानों के लिए बहुत कुछ होगा। देशभर के किसानों को उनकी भाषा में ही सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। पूसा संस्थान के खेतों में प्रदर्शनी के लिए लगाई गई उम्दा फसलों के उन्नत बीज भी किसानों को मौके पर ही उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकारी व गैरसरकारी कंपनियों व अनुसंधान संस्थानों के स्टालों पर सभी तरह के बीज व अन्य वस्तुएं मुहैया होंगी।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे राष्ट्रीय कृषि उन्नति मेला का उदघाटन
- जिंस मंडियों के वैश्वीकरण से खेती में बढ़ी प्रतिस्पर्धा : कृषि मंत्री

सुदूर गांवों से आए किसानों के लिए सजीव प्रदर्शन किया गया है। मेला परिसर के चार बड़े ब्लॉक में कृषि, बागवानी, पशुपालन, नवीन प्रौद्योगिकी और कृषि यंत्रों का प्रदर्शन किया गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार का पूरा ध्यान खेती की लागत को घटाने और उपज का उचित मूल्य दिलाने पर है। इसी फार्मूले से किसानों की आय को अगले कुछ साल में दोगुना करना संभव हो पाएगा। इसके लिए सरकार ने आम बजट में बहुत कुछ उपाय किए हैं, जिन्हें लागू करने के लिए राज्यों पर लगातार दबाव बनाए हुए है। मेले की थीम पैवेलियन को आठ जोन में बांटा गया है। इसमें एग्रो क्लामेटिक जोन, सिंचाई, मिट्टी, प्रौद्योगिकी, पशु पालन व मछली पालन, कृषि पुनरोद्धार व बागवानी के साथ जुड़े अन्य क्षेत्रों को दर्शाया गया है।

पृ0-7

संसद मार्ग पर किसानों ने की पंचायत, मांगा हक

संसद मार्ग पर बृहस्पतिवार को विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन करतीं भारतीय किसान यूनियन की महिला कार्यकर्ता। जागरण

- भाकियू ने केंद्र पर लगाया किसानों की अनदेखी का आरोप

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के बैनर तले किसानों ने जंतर-मंतर पर पंचायत का आयोजन किया, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब समेत अन्य राज्यों के किसानों ने भाग लिया। पंचायत में केंद्र सरकार से किसानों को फसलों का उचित व लाभकारी मूल्य देने, किसानों की न्यूनतम आमदनी तय करने, जैव परिवर्तित फसलों पर रोक लगाने, फसल बीमा योजना को विस्तृत करने व मुक्त व्यापार समझौते में कृषि को न शामिल करने जैसी मांगें की गईं।

पंचायत को संबोधित करते हुए भाकियू के महासचिव युद्धवीर सिंह ने कहा कि किसानों ने केंद्र में भाजपा की सरकार बनवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद थी कि वह कृषि संकट से निपटने के लिए ठोस नीतियां बनाई जाएंगी, लेकिन सरकार के दो वर्षों के कार्यकाल में किसानों को कोई विशेष लाभ होता नहीं दिखाई दे रहा है। भाकियू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि भाजपा ने अपने चुनावी घोषणापत्र में किसानों को उनकी उत्पादन लागत में 50 फीसद जोड़कर समर्थन मूल्य देने का वादा किया था, लेकिन आज तक यह वादा पूरा नहीं हुआ है।

खराब मौसम और सूखे के कारण फसलों के बर्बाद होने और कर्ज में डूबे किसानों की आत्महत्या का सिलसिला जारी है। इसपर भी इन दो वर्षों में रोक नहीं लग सकी है। पंचायत में गन्ना किसानों के बकाया भुगतान पर भी चिंता व्यक्त की गई।

दीपक 18/3/16
उप प्रभारी, समाचार पत्र यूनिट